(a) whether the Government have conducted any survey to identify barren land in Karnataka; if so, the details thereof;

(b) whether any research has been conducted to make such land fertile by scientific methods; if so, the details thereof; and

(c) whether any barren land has been made fertile during the last one year and so far in 1996; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHAN-DRADEO PRASAD VERMA): (a) No survey has been conducted for the identification of barren land in Karnataka. However, department of Wastelands Development has commissioned National Wastelands Identification Project with the collaboration of National Remote Sensing Agency. Under this project, districts having more than 5% of geographical area as wastelands have been mapped. The districts covered are Bangalore, Belgaum, Bijapur, Bidar, Bellary, Chitadurga, Chikmagalur, Gulbarga, Hassan, Kolar, Mandya, Raichur, Shimoga and Tumkur, having a total of 1.71 million ha. of wastelands, including barren land in the State.

(b) and (c) The Department of Wastelands Development is implementing the following schemes for Development of wastelands. The area treated in Karnataka during 1995-96 is indicated against each scheme:

Scheme	Area covered during 1995-96 (in ha.)
1. Integrated Wastelands Development Projects	2675
2. Technology Development Extension & Training	100
3. Grants-in-Aid to Voluntry Agencies.	330

पन बिजली परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा

457. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाई गई पन बिजली परियोजनाओं में पंजाब और हरियाणा सरकारों से अपना हिस्सा प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार से बार-बार अनुरोध करती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को अब तक कितनी सहायता उपलब्ध कराई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) जी, हां हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश में स्थित भाखड़ा-नांगल और व्यास परियोजना के चालू होने की तिथि से 7.19% की बढ़ी हुई हकदारी और 12% निःशुल्क विद्युत के हिस्से के लिए अपना दावा करती रही है। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने मामले में निर्णय हेतु प्रार्थना करते हुए उच्चतम न्यायालय में जून, 1996 में एक याचिका भी दायर की है।

(ग) राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम की केन्द्रीय क्षेत्र वाली परियोजनाओं यथा; बैरा स्यूल (198 मे०वा०) और चमेरा चरण-1 (540 मे०वा०) से 12% निःशुल्क विद्युत हिमाचल प्रदेश राज्य को प्रदान की गयी है। राज्य को उसकी विद्युत ऊर्जा और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतःराज्यीय अंतरण की सुविधा भी प्रदान की जाती है। अप्रैल-मई, 1996 के दौरान हिमाचल प्रदेश को पश्चिमी क्षेत्र के अतिरिक्त पंजाब और उत्तर प्रदेश से 85.1 मि०यू० विद्युत प्रदान की गयी है।

Kayamkulam Thermal Power Project

458. SHRI M.A. BABY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of the present stage of the Kayamkulam Thermal Power Project;

(b) the details regarding the financial tic up for the above project;

(c) the expected date of the award of the main plant contract; and

(d) the details of the time schedule of commissioning of the entire project?